अध्याय–IV

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करना और विशेष योग्यजनों का कल्याण

अध्याय–IV

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करना और विशेष योग्यजनों का कल्याण

सवाईमाधोपुर और उदयपुर जिलों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तरों पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित थे।

विशेष योग्यजन साक्षरता दर (40.16 प्रतिशत) में राजस्थान नीचे से दूसरे स्थान (35 में से 34 वां स्थान) पर था। स्कूली शिक्षा के लिए नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 2016-17 में 1.07 लाख से घटकर 2020-21 में 0.75 लाख हो गए, जो 30 प्रतिशत की कमी है। आवश्यक मानव संसाधन की कमी थी जैसे राजकीय विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के पद (38.10 प्रतिशत) तथा संसाधन केन्द्रों पर 357 संसाधन व्यक्तियों के पद (56.22 प्रतिशत) रिक्त थे।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों में विशेष योग्यजनों के लिए स्पीच थेरेपिस्ट/ऑडियोलॉजिस्ट/फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति नहीं पाई गई। निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण/प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण में अत्यधिक विलंब हुआ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) प्रावधित करती है कि "दिव्यांग व्यक्ति" से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रूकावट उत्पन्न होती है इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) प्रावधित करती हैं कि संदर्भित दिव्यांग व्यक्ति का अर्थ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान करता है और उन उपायों का प्रावधान करता है जो सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को समावेशी शिक्षा की प्रणाली को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। अधिनियम बाध्य करता है कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को बिना किसी भेदभाव के इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

4.1 विशेष योग्यजनों की पहचान और दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करना

दिव्यांगजनों के सभी अधिकार और हक़दारियां तथा भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के लाभ संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, जिसके लिए प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी एक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)[47], जो पूरे देश में मान्य है, जारी करने की प्रक्रिया के चरण **चार्ट 2** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2: दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

(i) लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई-अगस्त 2021) में पाया गया कि राजस्थान में, 2011 की जनगणना में 15.64 लाख विशेष योग्यजनों की पहचान की गई थी, जिसके विरुद्ध मार्च 2021 तक 11.17 लाख (71.42 प्रतिशत) पंजीकृत किए गए थे। आठ नमूना जांच किए गए जिलों में इस संबंध में स्थिति नीचे **तालिका 1** में दर्शायी गयी है:

47 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक विशेष योग्यजन को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से यूडीआईडी परियोजना को लागू किया।

तालिका 1

नमूना जांच किये गये जिले	2011 की जनगणना के अनुसार विशेष योग्यजनों की संख्या	जिले में पंजीकरण की संख्या	कमी *(प्रतिशत)*
बाड़मेर	56,183	32,617	23,566 *(41.94)*
बीकानेर	37,898	32,421	5,477 *(14.45)*
डूंगरपुर	33,774	18,847	14,927 *(44.19)*
जोधपुर	91,730	57,286	34,444 *(37.55)*
कोटा	44,859	33,939	10,920 *(24.34)*
सवाईमाधोपुर	32,563	15,345	17,218 *(52.87)*
टोंक	40,510	23,745	16,765 *(41.38)*
उदयपुर	82,270	25,296	56,974 *(69.25)*

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि सवाईमाधोपुर और उदयपुर जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी। जबकि राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया गया था, जैसा कि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के निर्देश (नवंबर 2017) में 50 प्रतिशत से कम पंजीकरण वाले जिलों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए थे, विभाग द्वारा इस संबंध में बहुत कम ध्यान दिया गया था। क्योंकि वर्ष 2017-18 में आयोजित 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर' अभियान के बाद राज्य में कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया।

(ii) इसके अलावा, अभिलेखों की जांच और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के विश्लेषण से पता चला कि विभाग के पास पंजीकृत आवेदनों के निस्तारण में महत्वपूर्ण विलम्ब रहा। 2017-21 के दौरान दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पंजीकृत आवेदनों, जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों, अस्वीकृत आवेदनों और लंबित आवेदनों का विवरण नीचे **तालिका 2** में दिया गया है:

तालिका 2

वर्ष	पंजीकृत आवेदन	जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	अस्वीकृत आवेदन	निदान के लिए ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा महाविद्यालय/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास लंबित
2017-18[48]	9,54,850	2,42,489	सूचना उपलब्ध नहीं है	5,46,041
2018-19	10,12,969	3,17,606	1,11,846	4,46,566
2019-20	10,64,540	3,58,943	1,23,435	4,10,362
2020-21	11,17,160	3,94,496	1,32,054	3,05,557

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना। तालिका में आंकड़े प्रगतिशील आंकड़े हैं।

48 21 मार्च 2018 की स्थिति।

विभाग द्वारा 2016-17 से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई (जुलाई 2021-जनवरी 2022)।

तालिका से देखा जा सकता है कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पंजीकृत 11,17,160 आवेदनों में से, मार्च 2021 तक 1,32,054 आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। शेष 9,85,106 आवेदनों में से, राज्य में विशेष योग्यजनों को केवल 3,94,496 दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (40.05 प्रतिशत) जारी किए गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3,05,557 आवेदन (31.01 प्रतिशत) ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (1,72,710), प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (36,351), चिकित्सा महाविद्यालय (94,232) और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (2,264) के पास निदान के लिए लम्बित थे, जिसके कारण उन्हें दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संसाधित नहीं किया जा सका। जबकि 2017-21 की अवधि के दौरान लम्बित आवेदन कम हुए, आवेदनों के निस्तारण की दर पर्याप्त नहीं थी जैसा कि मार्च 2021 तक महत्वपूर्ण लम्बित से परिलक्षित होता है। विभाग द्वारा जिन आवेदनों पर आपत्ति की गई थी, उनका विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि संबंधित आवेदकों को मोबाइल पर संदेश के माध्यम से सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने रुचि नहीं ली और इन आवेदनों को रोक कर रखा गया।

आवेदनों का समय पर संसाधन के अभाव में, बड़ी संख्या में विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सका और इस प्रकार वे लंबे समय तक विभिन्न लाभों से वंचित रहे।

अनुशंसा 7: *राज्य सरकार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए विशेष योग्यजनों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चला सकती है और आवेदनों के निस्तारण के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा के संबंध में मानदंड निर्धारित कर सकती है।*

4.2 शिक्षा

दिव्यांगता औपचारिक शिक्षा में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है। विशेष योग्यजनों की शैक्षिक उपलब्धि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और सार्वजनिक जीवन में सम्मान के साथ उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

(i) शैक्षिक संस्थानों में विशेष योग्यजन बच्चों का नामांकन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16 में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रयास करेगी कि उनके द्वारा सभी वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 31 अनिवार्य

करती है कि छह से 18 वर्ष तक के संदर्भित दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को उसकी पसंद के निकटवर्ती विद्यालय या किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई-अगस्त 2021) में पाया गया कि राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शैक्षिक लक्ष्य में महत्वपूर्ण कमी रही। 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 5-19 वर्ष के आयु वर्ग में 3,06,750 दिव्यांग बच्चे थे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (रास्कूशिप) ने राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन को सूचित किया (अगस्त 2021) कि सत्र 2020-21 के दौरान केवल 75,495 विशेष आवश्यकता वाले बच्चें (सीडब्ल्यूएसएन) विद्यालयों (निजी, राजकीय और सरकारी सहायता प्राप्त) में नामांकित किये गये थे। इससे पता चलता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की एक महत्वपूर्ण संख्या को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित नहीं किया गया है। वास्तव में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन में 2016-21 की अवधि के दौरान गिरावट आई है जैसा कि **चार्ट 3** में दर्शाया गया है:

चार्ट 3: सत्र 2016-21 के दौरान विद्यालयों में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या

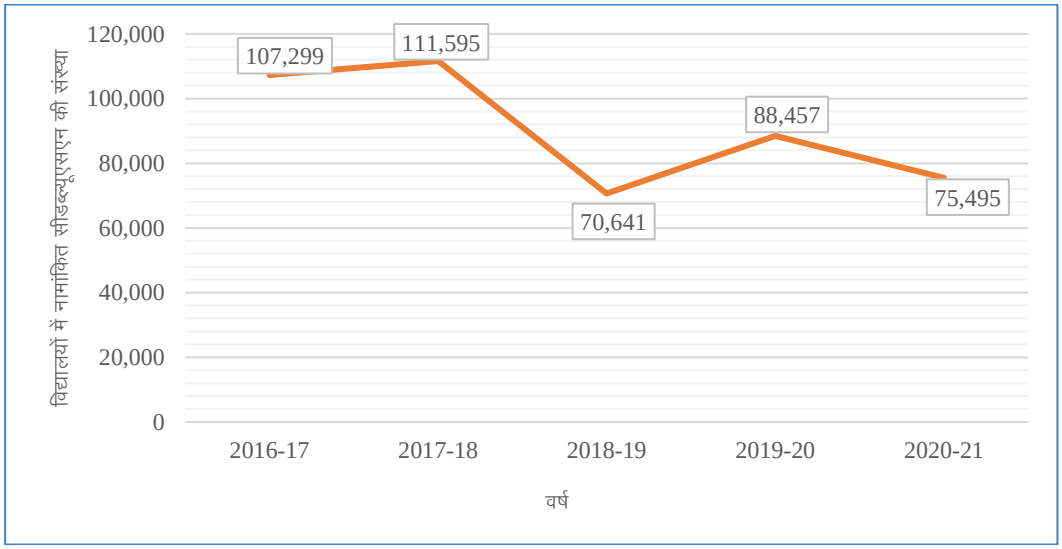

स्रोतः राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

चार्ट में दर्शाया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन 2016-17 में 1,07,299 से घटकर 2020-21 में 75,495 हो गया, जो 30 प्रतिशत की कमी है।

विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कम नामांकन के परिणामस्वरूप राज्य में विशेष योग्यजनों के बीच साक्षरता की स्थिति खराब हो गई है। प्रतिवेदन पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) इन इंडिया-ए स्टैटिकल प्रोफाइलः 2021 भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, के अनुसार राजस्थान को देश में विशेष योग्यजनों की साक्षरता दर (40.16 प्रतिशत) में दूसरा

सबसे कम (35 में से 34 वां स्थान) स्थान दिया गया था। राजस्थान में विशेष योग्यजनों के बीच साक्षरता **चार्ट 4** में दी गई है:

चार्ट 4: जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग के आधार पर विशेष योग्यजनों की साक्षरता स्थिति

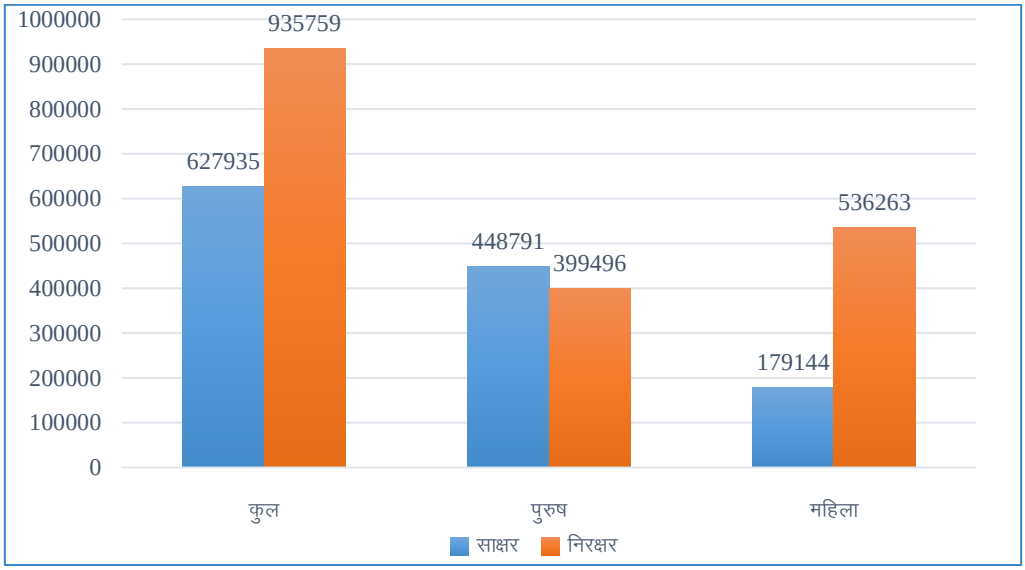

स्रोत: पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) इन इंडिया- ए स्टैटिकल प्रोफाइल 2021 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

चार्ट दर्शाता है कि राजस्थान में, 59.84 प्रतिशत विशेष योग्यजन साक्षर नहीं थे । इसके अलावा, महिला विशेष योग्यजन में, 74.96 प्रतिशत (5,36,263) साक्षर नहीं थे, की तुलना में 47.09 प्रतिशत (3,99,496) पुरुष विशेष योग्यजन जो निरक्षर थे ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि इस धारा के अनुपालन हेतु समावेशी शिक्षा अभियान के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है । इसके अलावा, विशेष योग्यजन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकते थे और विशेष योग्यजन को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से राज्य में 110 विशेष विद्यालय संचालित किये जा रहे थे ।

अनुशंसा 8: *राज्य सरकार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर सकती है।*

(ii) शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि राज्य सरकार समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के उपाय करेगी जैसे विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिये सर्वेक्षण संचालित करना, संसाधन केंद्र और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और नियोजित करना आदि ।

यह देखा गया कि राज्य सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छः जिलों में विशेष शिक्षकों[49] वाले सात राजकीय विशेष विद्यालयों[50] का संचालन कर रही थी। इसके अलावा, राज्य के विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं को उनकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक शैक्षिक और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों के साथ राज्य में संसाधन केंद्र भी विकसित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2021-जनवरी 2022) में पाया गया कि इन विशेष विद्यालयों और संसाधन केंद्रों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। यह देखा गया कि:

(अ) सत्र 2020-21 में 1131 विद्यार्थियों वाले 7 राजकीय विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत 105 पदों के विरुद्ध मात्र 65 शिक्षक (61.90 प्रतिशत) कार्यरत थे।

(ब) राज्य में संसाधन व्यक्तियों के 635 पदों[51] के विरूद्ध मार्च 2021 तक 357 पद (56.22 प्रतिशत) रिक्त थे। आठ नमूना जांच किए गए जिलों में, स्वीकृत 234 संसाधन व्यक्तियों के विरुद्ध, मार्च 2021 तक 149 पद (63.67 प्रतिशत) रिक्त थे, जिसमें टोंक में 22.22 प्रतिशत से लेकर उदयपुर में 92.16 प्रतिशत तक रिक्तियां थीं।

विशेष शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या के अभाव में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपेक्षित शैक्षिक और चिकित्सीय सहायता प्रदान नहीं की जा सकी।

4.3 विशेष योग्यजनों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली

राजस्थान में, मार्च 2021 तक 31 जिलों में 101 विशेष विद्यालय (आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालय) स्थापित किए गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को इन आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत/वास्तविक कर्मचारियों[52] (जो भी कम हो) के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार, राजस्थान सरकार गैर सरकारी संगठनों को आवासीय विद्यालयों में आवास कर रहे आवासियों के आधार पर भोजन भत्ता प्रदान करती हैं।

49 एक विशेष शिक्षक एक शिक्षक होता है जो सभी उम्र के बच्चों के साथ काम करता है जिनकी विशेष जरूरतें होती हैं चाहे वे संज्ञानात्मक, भावनात्मक या शारीरिक हों।

50 मूक-बधिर विद्यालयः 03 और नेत्रहीन विद्यालयः 04

51 जिला स्तरः 33 और खण्ड स्तरः 602

52 निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा गैर सरकारी संगठनों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यदि गैर सरकारी संगठन मानदंडों से कम पदस्थापित करता है, तो निदेशालय, विशेष योग्यजन गैर सरकारी संगठन को नियुक्त कर्मचारियों के अनुसार अनुदान जारी करता है।

4.3.1 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना

निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों को जारी अनुदान की शर्त के अनुसार, विशेष शिक्षकों को भारतीय पुनर्वास परिषद (भापुप) के मानदंडों के अनुसार योग्यताधारी होना चाहिए और विशेष शिक्षकों के उचित योग्यताधारी नहीं होने की स्थिति में, इन विशेष शिक्षकों को किये गये भुगतान की वसूली संस्था से किया जाना था । इसके अलावा, विभाग द्वारा शिक्षक विधार्थी अनुपात दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित विधार्थियों के विशेष विद्यालयों के लिए 1:15 और मानसिक विमंदित के विशेष विद्यालयों में 1:8 निर्धारित (2006 में) किया था ।

आठ नमूना जांच किए गए जिलों में 11 गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2021-जनवरी 2022) में पाया गया कि:

(i) दो गैर सरकारी संगठनों[53] द्वारा चलाए जा रहे दो विशेष विद्यालयों में भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत विशेष शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया गया था । हालांकि, ये गैर सरकारी संगठन निदेशालय, विशेष योग्यजन से अनुदान प्राप्त कर रहे थे । इंगित किए जाने पर, दोनों गैर सरकारी संगठनों ने तथ्यों को स्वीकार किया । इनमें से, एक गैर सरकारी संगठन[54] ने अवगत कराया (सितंबर 2021) कि उसने भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत शिक्षकों को नियोजित नहीं किया क्योंकि योग्यता प्राप्त शिक्षकों द्वारा उच्च वेतन की मांग की जिसे गैर सरकारी संगठन द्वारा वहन नहीं किया जा सकता ।

शिक्षकों की उचित योग्यता का अभाव विशेष विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है ।

(ii) 2016-21 के दौरान छः गैर-सरकारी संगठनों[55] द्वारा स्पीच थेरेपिस्ट/ ऑडियोलॉजिस्ट / फिजियोथेरेपिस्ट[56] की नियुक्ति नहीं की गई थी । राजस्थान

---

53 सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन माणकलाव, जोधपुर एवं विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर

54 विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर ।

55 (i) विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर (ii) वेलफेयर इंडिया सोसाइटी, कोटा (iii) तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान, डूंगरपुर (iv) सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी (श्योर) बाड़मेर (v) सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान, बीकानेर (vi) योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान, निवाई, टोंक ।

56 आयुक्त सह शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विद्यालय की श्रेणी के अनुसार विशेष विद्यालय में विषय में विशेषज्ञता रखने वाले एक स्पीच थेरेपिस्ट/ ऑडियोलॉजिस्ट/ फिजियोथेरेपिस्ट/ब्रेल शिक्षक/योग शिक्षक/मनोवैज्ञानिक की सेवाओं की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए (अप्रैल 2011) ।

सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि चिकित्सा विशेषज्ञ की नियुक्ति जिलों में अनुपलब्धता एवं कम मानदेय (बीकानेर एवं डूंगरपुर) के कारण नहीं की गयी थी।

ये उदाहरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए गैर सरकारी संगठनों को जारी अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा प्रभावी निगरानी की कमी को दर्शाते हैं।

4.4 संस्थानों का पंजीयन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 49 में प्रावधान है कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए संस्थानों के पंजीयन और ऐसे संस्थानों को अनुदान देने के उद्देश्य से एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 7 के अनुसार, संस्थान के पंजीयन के लिए निदेशक, निदेशालय, विशेष योग्यजन सक्षम प्राधिकारी होगा। तदनुसार, राजस्थान सरकार ने निदेशक, निदेशालय, विशेष योग्यजन को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त (जून 2018) किया। जिला कलेक्टर को मई 2018 तक गैर सरकारी संगठन के पंजीयन/नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

निदेशालय, विशेष योग्यजन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया (जुलाई-अगस्त 2021) कि निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा जुलाई 2018 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 184 गैर सरकारी संगठनों को पांच साल के लिए पंजीकृत किया गया था।

(i) ***नया पंजीयन स्वीकृत करना*** – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51 (2) प्रावधान करती है कि गैर सरकारी संगठनों से आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों की अवधि के भीतर आवेदक को पंजीयन का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करेगा। निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा सितंबर 2019 से मार्च 2021 के दौरान गैर सरकारी संगठनों के नए पंजीयन के लिए प्राप्त 23 आवेदनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 22 पंजीयन प्रमाण-पत्रों को स्वीकृत करने में प्रस्तुत करने की तिथि/जिला अधिकारी द्वारा भेजने की तिथि से 109 दिन से 526 दिन का समय लिया गया ***(विवरण परिशिष्ट -IV)***।

(ii) ***पंजीयन के नवीनीकरण को स्वीकृत करना*** – निदेशक, निदेशालय, विशेष योग्यजन ने आदेश जारी किए (जुलाई 2018) कि गैर सरकारी संगठन से पंजीयन प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के दिन से 60 दिनों के भीतर आवेदक को नवीनीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। गैर सरकारी संगठनों के पंजीयन के नवीनीकरण के 23 मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 17 प्रकरणों में, निदेशक, निदेशालय, विशेष योग्यजन ने 2018-21 के दौरान आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंजीकृत प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण के लिए 78 दिन से 529 दिन तक का समय लिया ***(विवरण परिशिष्ट-V)***।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (नवम्बर 2022) कि पंजीयन प्रमाण-पत्र आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद जारी किए जाते हैं और पंजीयन प्रमाण-पत्र समय पर जारी करना आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण बाधित हो सकता है । उत्तर में यह भी अवगत कराया कि प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है ।

अनुशंसा 9: *राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों का समय पर पंजीयन स्वीकृत करने और उनके नवीनीकरण के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर सकती है और गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी निगरानी के लिए उचित डेटाबेस तैयार कर सकती है ।*